



अधिकतम : 34°C
न्यूनतम : 20°C

अबने चुपचात नही, छापता है

शाह टाइम्स

मेरठ, गुरुवार 30 अप्रैल 2026 मेरठ संस्करण: वर्ष 19 अंक 328 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00



विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें।
सुपाने PDF E-paper

shahitimes2015@gmail.com

बैसाख शुक्र पक्ष 13 विक्रमी मखर 2083

11 जिल का 1447 जिला

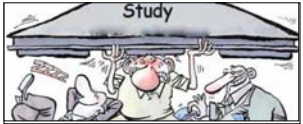
नई दिल्ली, मुम्बई, देहरादून, इटावा, मुदायबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित



यूपी विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारी, महिला आरक्षण पर सियासी घमासान तय पेज 2



राजस्थान रॉयल्स के सूर्यवंशी ने फिर किया ऑरेंज कैप पर कब्जा खेल टाइम्स



स्कूल की चौखट पर खड़ा बाजार, भीतर सिमटी शिक्षा सम्वादकीय



ईरान में हार से बचने को अमेरिका रास्ता तलाश रहा: अमेरिकी विशेषज्ञ पेज 12

संक्षिप्त समाचार

पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने संबंधी आदेश फर्जी: सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से संबंधित सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा आदेश फर्जी है और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है। सोशल मीडिया पर वायरल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के इस कथित आदेश में दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में दस रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में साढ़े बारह रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। कथित आदेश में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने इस बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कानूनीय पीओबी की फेक वेबसाइट में बुधवार को इस कथित आदेश की जांच की गई और यह फर्जी है और सरकार ने पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का कोई आदेश जारी नहीं किया है।

राजस्थान में गर्मी के चलते ट्रेन के ब्रेक में लगी आग

नई दिल्ली। देश के कई शहर रोजीव के चले हैं। जयपुर दिवसों में तामाम 40-46 डिग्री सेल्सियस के बीच है। मध्य प्रदेश के देवास में गर्मी से बचने के लिए 20 कुत्तार के साथ वाहन निकली हैं। राजस्थान के भीलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के एक जवान कोच के निचले हिस्से में आग लग गई। रेलवे के सूचों के मुताबिक, गर्मी के कारण ब्रेक फ्रैक्चर वाले हिस्से में आग लगी थी। ओडिशा के झारखंड में 43.3 डिग्री से ज्यादा तापमान रहा। बंगलूरु में भी आग लगी है। जहां ठंडा नहीं आती रेलगाड़ियां का ईंधन जलना। यूपी के 15 शहरों में ओपी-बारी हुई।

गाजियाबाद में आवासीय इमारत में आग लगने से हड़कंप

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के हीरोपुरम स्थित ग्रीन एन्वय सोसाइटी में बुधवार को भीषण आग जलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अनिश्चित आधिकारी ने घटनास्थल से जांचकर्ता रेले हुए बताया कि दमकल कर्मियों को टीम में बुलवाया पहुंचकर आग बुझाने का कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि, आग ऊंची मॉडलों तक फैल रही थी, इसलिए इस पर काबू पाने के लिए प्रेन को मोके पर लगाया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आग के दूर रहने तक भी फैलने की आशंका से कहां रह रहे लोगों में अफस-तफस मच गई है।

ग्रेट निकोबार परियोजना पर राहुल ने मांगा जवाब

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उद्घाटन-निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीपों में प्रस्तावित विकास परियोजना को लेकर सवादा उठाते हुए सरकार से इस पर स्पष्ट जवाब देने को कहा है। श्री गांधी ने 'एक्स' पर श्रेक के अपने हलिया दौर का विडक करते हुए कहा कि ग्रेट निकोबार के जंगल अत्यंत पवित्र और अप्रदूष हैं, जिन्हें विकसित होने में पीढ़ियां लगी हैं।

एविजट पोल: बंगाल में पहली बार भाजपा

असम, पुदुचेरी में भी खिलेगा कमल, तमिलनाडु में टीवीके आगे व केरल में यूडीएफ बनाएगी सरकार

बंगाल में आखिरी चरण में 92 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में 6 एविजट पोल के नतीजे आ चुके हैं। 5 में भाजपा और एक में टीएमसी सरकार बनने का अनुमान बताया गया है। मैट्रिज के एविजट पोल में टीएमसी को 125 से 140 और भाजपा को 146 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है। 'चाणक्य स्ट्रेटजी' ने टीएमसी को 130 से 140 और भाजपा को 150 से 160 सीटें मिलने का अनुमान बताया है। पीपुल्स परस ने टीएमसी को 177 से 187 और भाजपा को 95 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है। प्रजा पोल ने टीएमसी को 85 से 110 और भाजपा को 178 से 200 सीटें मिलने का अनुमान है। पी-मार्क के एविजट पोल में टीएमसी को 118 से 138 और भाजपा को 150 से 175 और सीटें दी गई हैं। पोल डायरी ने टीएमसी को 99 से 127 और भाजपा को 142 से 171 सीटें मिलने का अनुमान है। असम के 8 एविजट पोल सामने आए हैं, सभी में भाजपा की वापसी का दावा किया गया है। एक्सप्रेस माप डीजल ने भाजपा को 24-36 सीटें मिलने का अनुमान बताया है। मैट्रिज ने भाजपा को 85-95 और कांग्रेस को 23-32 सीटें दी हैं। पीपुल्स परस ने 23-32 सीटें दी हैं। पीपुल्स परस ने

एजेंसी	TMC	BJP	अन्य
मैट्रिज	125-140	146-161	6-10
चाणक्य स्ट्रेटजी	130-140	150-160	0-5
पीपुल्स परस	177-187	95-110	1-4
पोल डायरी	99-127	142-171	5-9
प्रजा पोल	85-110	178-208	0-5
पी मार्क	118-138	150-175	0-0
जगमत पोल	195-205	80-90	1-4
एवेजट	142	145	7

भाजपा को 68-72 और कांग्रेस को 22-26 सीटें दी हैं। पी मार्क ने भाजपा को 82-94 और कांग्रेस को 30-40 सीटें दी हैं। जैवैसी को 88-101 और कांग्रेस को 23-33 सीटें का अनुमान बताया है। चाणक्य स्ट्रेटजी ने भाजपा को 88-98 और कांग्रेस को 22-32 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल डायरी ने भाजपा को 86-101 और कांग्रेस को 15-26 सीटें मिलने का अनुमान बताया है। वोट डायरी ने भाजपा को 90-101 और कांग्रेस को 23-33 सीटें दी हैं। तमिलनाडु के 5 एविजट पोल-4 में टीएमसी को वापसी बताई गई है। मैट्रिज ने टीएमसी को 122-132, एआरके डीएमके को 87-110 सीटें मिलने का अनुमान बताया है। पी मार्क ने टीएमसी को 125-145, एआरडीएमके को 65-85 सीटें दी हैं। पीपुल्स परस ने टीएमसी को 120-140, एआरडीएमके को 60-70 सीटें दी हैं। जैवैसी-वदरस माड डीएमके को 75-95 एआरडीएमके को 128-147 सीटें दी हैं। पीपुल्स परस ने टीएमसी को 125-145 एआरडीएमके को 65-80 सीटें मिलने का अनुमान बताया है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सकेड फेज की 142 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, 92 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई है। यह और बढ़ सकता है।

वोटिंग के दौरान कई जगहों पर हिंसा, झड़प, लाठीचार्ज और ईवीएम से छेड़छाड़ की घटनाएँ सामने आईं। नॉर्थ 24 परगना के अरविंद देवी में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को दौड़ा-दौड़ाकर धक्के, लाठियों से हमले किए। भारी संख्या में सुरक्षाबलों को मौजूदगी के बावजूद हालात बेकाबू दिखे। सीएम मतात ने सीआरपीएफ पर टीएमसी समर्थकों और वोटों से मारपीट का आरोप लगाया। मतात ने कहा कि सीआरपीएफ ने हमारे कई लोगों को गिरफ्तार किया है। वोटों और सेंट्रल अक्सिडेंट को भी मार रहे हैं। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। टीएमसी ने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ के हमले से हावड़ा के

उत्तर 24 परगना में टीएमसी-भाजपा कार्यकर्ताओं में हिंसा दावा: हावड़ा में CRPF की पिटाई से बुजुर्ग की मौत

उदयनारायणपुर में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि बुजुर्ग अपने बेटे के साथ बोल डालने गए थे। केंद्रीय बलों ने उन्हें धक्का दिया और मारपीट की। बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जिन 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उनमें से 123 सीटों पर टीएमसी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। पहले फेज की 152 सीटों पर 23 अप्रैल को रिकॉर्ड 93 फीसदी मतदान हुआ था। 4 मई को रिजल्ट आएंगे।



शुवेदु अधिकारी को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घेरा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान कई विधानसभा सीटों पर हिंसा और मारपीट की घटनाएँ सामने आईं। नादिया जिले के छत्रा में भाजपा नेता ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। वहाँ, शांतिपुर में भाजपा कैंप पर भी हमला हुआ। बीजपुर में निर्दलीय प्रचारपीठ और काउंसिलर के बीच मारपीट हो गई। श्यामपुर में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा उम्मीदवार रत्ना देवनाथ ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। वहाँ बंगाल में ऑरिज चरण के साथ मतदान संपन्न हो गया है। अब मतगणना चार मई को होगी। इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरे देश में सुर्खियों में बना रहा है।

ईरान को NPT का उपाध्यक्ष बनाने पर तिलमिलाया अमेरिका

न्यूयॉर्क। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। इसी बीच एक दिलचस्प खबर सामने आई है। ईरान को परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) का उपाध्यक्ष चुना गया है। यह फैसला न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के चले रहे एनपीटी के 11 वें रिज्यू-कॉन्फ्रेंस में लिया गया। यह कॉन्फ्रेंस 5 साल में एक बार होती है। सम्मेलन के अध्यक्ष और विधानसभा के राजदूत दी गुंटा विरिन्डे ने बताया कि ईरान का नाम 'गुटनियम देशों के ग्रुप' की तरफ से आया था। इस ग्रुप में भारत समेत 100 से भी ज्यादा देश हैं। अमेरिका के एक अधिकारी क्रिस्टोफर वेनो ने इसे एनपीटी के लिए अमान्य

तीस्ता सौतलवाड़ की अजी खारिज

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेर्रेस 27 अप्रैल 2026 को युएन हर्डकवॉटर में परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हुई मॉटिंग में प्रतिनिधियों का संबोधित करते हुए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेर्रेस 27 अप्रैल 2026 को युएन हर्डकवॉटर में परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हुई मॉटिंग में प्रतिनिधियों का संबोधित करते हुए। परमाणु अप्रसार संधि 1970 में लागू हुई थी। यह दुनिया में परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने की सबसे अहम व्यवस्था मानी जाती है। इस संधि का एक सौधा सौदा है, जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं हैं, वे उन्हें नहीं बनाएंगे और जिनके पास हैं, वे धीरे-धीरे उन्हें खत्म करेंगे।

सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं कर सकते: SC

नई दिल्ली। केरलम के सबरीमाला मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने एडवोकेट शेरिफा जयसिंह को दलीलों के जवाब में जवाब देना सौचित्य सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता। आस्था और विवेक के मामले पर कोर्ट में बहस नहीं हो सकती। एडवोकेट जयसिंह ने सुनवाई के 10वें दिन कहा कि सबरीमाला मंदिर में एंट्री का फैसला अब भी लागू है। इस पर स्टे नहीं है, लेकिन मंदिर में प्रवेश

सौगात: पीएम ने गंगा एक्सप्रेसवे किया राष्ट्र को समर्पित

उप के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाली लाइफलाइन साबित होगा एक्सप्रेसवे

शाह टाइम्स संवाददाता

हरदोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यहां 594 किलोमीटर लंबी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और देश के साथ ही उत्तर प्रदेश के अवसरचन्ना विकास में ऐतिहासिक अंधाधुंध युग समाप्त। यह लम्बी कीर्नोन्डिक्टिवी और ऑफिक महत्वाकांक्षीओं में एक महत्वपूर्ण काम है। प्रधानमंत्री ने स्थल पर एक पौधा लगाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक्सप्रेसवे पर पैदल चक्कर इकट्ठे हुए। पीएम को ग्रेट निकोबार के जंगल अत्यंत पवित्र और अप्रदूष हैं, जिन्हें विकसित होने में पीढ़ियां लगी हैं।



केसरा प्रसाद मोदी और बुधेश पाठक, साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी भी उपस्थित थे।

विपक्ष को सजा देने को बहन-बेटियों ने किया रिकॉर्ड मतदान: मोदी हरदोई। देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राजा की जीत का भरोसा जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करने वाले विपक्ष की कुटिल मंशा को बहन-बेटियां पर ध्यान नहीं दें। यह भी कारण है कि असम, केरलम, पुदुचेरी, बंगाल और तमिलनाडु में बहनों ने रिकॉर्ड मतदान किया है। हरदोई के मल्लोबा में देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के अवसर पर श्री मोदी ने आर्गोजिज एक जनसभा में कहा कि आज हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर भारत की बेटियां इतना शानदार काम कर रही हैं, तो राष्ट्र के भावित्व से जुड़े फैसलों में भी बहनों-बेटियों की भूमिका आम बननी ही चाहिए।

सूत्रों पर दिखा हैक का मैसैज, गांधी भी बजे क्षितिजों सिंह थे। शरद्वारी पुष्टागत में क्षितिजों ने दावा किया कि उनका अकाउंट अमेरिका से हैक किया गया था। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि सुनवाई के दौरान बह अश्लील वीडियो कैसे चला। बुधवार को सुनवाई के दौरान वीडियो चलने के बाद आपका सिस्टम हैक हो गया है', का मैसैज भी स्क्रीन पर दिखाई दिया। दो बार पॉप वीडियो चलने और लोसी बार वीडियो वीडियो चला। कोर्ट में 100 से ज्यादा जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, ये मामला उच्च दौरे समान आया।

अब 4 मई पर नजर

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। बुधवार को 142 सीटों पर मतदान हुआ। छह बजे तक आंकड़ों के अनुसार 91 प्रतिशत से अधिक मतदान हो चुका था और यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह और अधिक बढ़ सकता है। पहले चरण का मतदान जो 152 सीटों पर 23 अप्रैल को हुआ था, उसमें भी रिकॉर्ड 93 फीसदी मतदान हुआ था। मत प्रतिशत बढ़ने को लेकर राजनीतिक पंडित भी एक राय नहीं बना पा रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह रूझान टीएमसी के पक्ष में जा सकता है, तो ऐसे लोगों को भी कमी नहीं है जो कहते हैं कि यह भाजपा के पक्ष में जाएगा। जैसाकि होता है चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल का दौर शुरू हो जाता है। बताते चलें कि पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम में चुनाव हुए हैं। लेकिन चर्चाओं में पश्चिम बंगाल का चुनाव ही अधिक रहा है। अगर हम यह कहें कि इसे भाजपा ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है तो गलत नहीं होगा। यह प्रतिष्ठा का ही सवाल है कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम कैबिनेट व भाजपा और उसके सहयोगी संगठन आरएसएस ने वहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन तमाम लव लश्कर को देखते हुए यह उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा पश्चिम बंगाल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ने जा रही है और भाजपा दावा भी कर रही है कि वह पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। छह एग्जिट पोल के नतीजे भी उसकी सोच को सही साबित भी करते हैं। छह में से केवल एक में ही टीएमसी जीतती दिखाई दे रही है। असम में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। केरल में जेरू बाजी कांग्रेस के हाथ जाती दिखाई दे रही हो, तमिलनाडु में पांच में से चार एग्जिट पोल में डीएमके की वापसी होती दिखाई दे रही है। जाहिर है चुनाव के बाद एग्जिट पोल में तमाम तरह की राय जाहिर की जाती है और अनुभव बताता है कि कई बार ये पोल गलत साबित होते रहे हैं। इसलिए असल पता तभी चलेगा जब 4 मई को चुनाव परिणाम सामने आएंगे, लेकिन असल बात इस समय यह है कि दूसरे चरण में जिस तरह का माहौल पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, वह हमारे लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। भले ही चुनाव प्रतिशत बढ़ा हो, लेकिन जिस तरह वहां से कई स्थानों पर हिंसा की खबरें आई हैं, जिसमें एक बूजुर्ग तक की जान चली गई है। वह बताता है कि अभी लोगों में इतना धैर्य नहीं आया है कि वह शांतिपूर्वक तरीके से मतदान कर सके और यह तब हुआ जब प. बंगाल में सुरक्षाबलों की अशुभपूर्व उपस्थिति बताई गई है। प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीएसएफ व सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय बलों ने जमकर भय का माहौल बनाया और लोगों को पीटा व गिरफ्तार किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अपने जीवन में उन्होंने ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। एसआईआर को लेकर पहले से ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता संदेह के घेरे में रही है।

रोजगार, आस्था व संस्कृति का होगा संरक्षण

देश का सबसे बड़ा 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे अन्नदाता किसानों की उन्नति, युवाओं के रोजगार, आस्था व संस्कृति के संरक्षण तथा उत्तर प्रदेश की समृद्धि का प्रमुख माध्यम साबित होगा, मंत्र से प्रयागराज तक फैले इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने 12 जनपदों के एक लाख से अधिक किसानों के योगदान से आकार लिया है, एक्सप्रेसवे के साथ-साथ 27 स्थानों पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक हब विकसित किए जा रहे हैं, जो न केवल आवागमन को तेज करेंगे, बल्कि नए निवेश और रोजगार के द्वार भी खोलेंगे, डबल इंजन सरकार की दूरदर्शिता का प्रतीक यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है, डबल इंजन सरकार का संकल्प है कि जिस परियोजना का शिलान्यास होगा, उसका उद्घाटन भी सुनिश्चित किया जाएगा। -योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उप्र

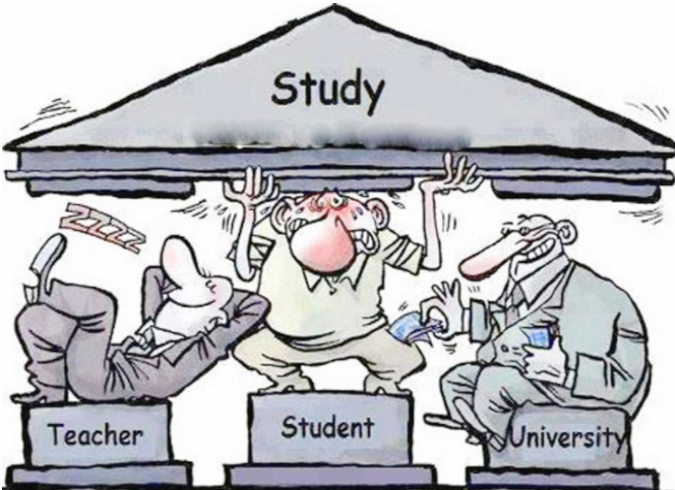


निजी विद्यालयों में एनसीईआरटी पुस्तकों के अनुपालन का सवाल अब महज पाठ्य सामग्री का विवाद नहीं रहा, बल्कि यह देश की शिक्षा व्यवस्था के चरित्र की परीक्षा बन चुका है। जब एक ओर कानून स्पष्ट दिशा देता हो और दूसरी ओर संस्थान स्वार्थवश उससे भटकें, तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि नैतिक विचलन का संकेत होता है। अप्रैल 2026 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा केंद्र, सीबीएसई और सभी राज्यों को जारी नोटिस ने इस विडंबना को उजागर किया है। यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक है कि क्या शिक्षा का अधिकार कानून केवल औपचारिक घोषणा बनकर रह गया है, या उसे लागू करने की प्रतिबद्धता ही क्षीण हो गई है। यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि शिक्षा में समानता का मूल सिद्धांत निरंतर दबाव और उपेक्षा के बीच संघर्ष कर रहा है।

शिक्षा का अधिकार कानून 2009 की धारा 29 ने स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया था कि प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) में पाठ्यक्रम और शिक्षापुस्तकों का निर्धारण एनसीईआरटी या संबंधित एनसीईआरटी द्वारा किया जाएगा। इसी सोच के तहत एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के निर्धारण का अधिकार सौंपा गया। इन संस्थाओं द्वारा तैयार पुस्तकें न केवल शैक्षणिक रूप से संतुलित और विश्वसनीय होती हैं, बल्कि आम परिवारों के लिए किफायती भी रहती हैं। इसके विपरीत, निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें इस मूल उद्देश्य को कमजोर करती हैं। जब एक ही कक्षा की पुस्तकों पर हजारों रुपये खर्च होने लगें, तो यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि क्या शिक्षा अब अधिकार से ज्यादा एक लाभकारी व्यापार में बदलती जा रही है।

निजी विद्यालयों में महंगी पुस्तकों को अनिवार्य बनाना कोई आकस्मिक भूल नहीं, बल्कि एक सूक्ष्मरहित आर्थिक तंत्र की ओर संकेत करता है। कई स्थानों पर स्कूल और प्रकाशक मिलकर ऐसा गडजोड़ रचते हैं, जिसमें शिक्षा का उद्देश्य पीछे छूट जाता है और मुनाफा केंद्र में आ जाता है। अभिभावकों को हठुच्च गुणवत्ता और हर्षाधिक उपयोगी सामग्री का हवाला देकर इन पुस्तकों को खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, जबकि इन दावों को ठोस पुष्टि प्रायः नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया में अभिभावकों की विवशता का व्यवस्थित दोहन होता है और वे विरोध करने में असहाय महसूस करते हैं। ऐसी प्रवृत्ति शिक्षा के नैतिक आधार को कमजोर करती है और संस्थागत विश्वसनीयता पर

स्कूल की चौखट पर खड़ा बाजार, भीतर सिमटती शिक्षा



गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती है। सबसे चिंताजनक परिणाम एक तेजी से गहराते शिक्षा-विभाजन के रूप में सामने आता है। जहां सरकारी विद्यालयों के बच्चे सस्ती, मानकीकृत और समान पुस्तकों से पढ़ते हैं, वहीं निजी स्कूलों के छात्र महंगी और अलग सामग्री पर निर्भर होते हैं, जिससे उनके ज्ञान का आधार ही भिन्न बन जाता है। यही अंतर आम चलकर अवसरों की खाई को और चौड़ा कर देता है। मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार पहले से ही शिक्षा पर बढ़ते खर्चों का दबाव झेल रहे हैं, ऐसे में किताबों का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उनके लिए बेहद असहनीय हो जाता है। यह स्थिति केवल आर्थिक असमानता को नहीं बढ़ाती, बल्कि समाज में गहराते असंतुलन और विभाजन को भी और मजबूत करती है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहल एक महत्वपूर्ण और समयोचित हस्तक्षेप के रूप में सामने आती है, जिसने शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार के व्यापक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता को

और स्पष्ट किया है। अनावश्यक तथा भारी-भरकम पुस्तकों का बढ़ता बोझ बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जो राष्ट्रीय स्कूल बैग पॉलिसी 2020 की मूल भावना के विपरीत है। यदि राज्य सरकारों और संबंधित संस्थाएं अब भी इस मुद्दे पर उदासीन बनी रहती हैं, तो यह केवल प्रशासनिक अक्षमता नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्वों की स्पष्ट उपेक्षा मानी जाएगी। इसलिए इस विषय को अब सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए टोस और प्रभावी कदम उठाना अनिवार्य हो गया है।

प्रो. आर.के. जैन



द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार होती हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता सिद्ध होती है। इसके विपरीत, निजी प्रकाशकों में आकर्षण अधिक, पर सामग्री की प्रमाणिकता पर सवाल बने रहते हैं। ऐसे में अकादमिक स्वतंत्रता के नाम पर व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देना शिक्षा की मूल भावना के विरुद्ध है। अब समय महज चर्चा का नहीं, टोस और निर्णायक हस्तक्षेप का है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर एक राफदशी, कड़ा और जवाबदेह निगरानी तंत्र विकसित करना होगा, जो कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर प्रभावी दिखे। निजी विद्यालयों की पुस्तक सूचियों का नियमित, निष्पक्ष और व्यापक ऑडिट सुनिश्चित किया जाए, तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर सख्त और उदाहरणमूलक कार्रवाई हो। जर्मनी से लेकर मान्यता रह करने तक के प्रावधानों को पूरी दृढ़ता के साथ लागू करना अनिवार्य है। साथ ही अभिभावकों को जागरूक और सशक्त बनाना होगा, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और किसी भी अनावश्यक आर्थिक बोझ के विरुद्ध निर्भीक होकर आवाज उठा सकें।

आखिरकार यह प्रश्न केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य और उसकी सामाजिक दिशा से गहराई से जुड़ा है। शिक्षा वही मजबूत आधार है जिस पर एक संतुलित और न्यायपूर्ण समाज की इमारत खड़ी होती है, और यदि इसी आधार में असमानता की दरार पड़ जाए, तो समावेशी विकास का सपना अधूरा रह जाता है। समान पाठ्य सामग्री सिर्फ शैक्षणिक जरूरत नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और अवसर की समानता का एक अहम स्तंभ है। अब सरकार और समाजकूदीनों के सामने यह स्पष्ट विकल्प है कि शिक्षा को बराबरी का सेतु बनाया जाए या उसे विभाजन की खाई में बदलने दिया जाए।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

वाहनों की बात करें तो उनके लिए इसका असर मिश्रित है।

अप्रैल 2023 से बने वाहन E20 कंप्लायंट हैं, वे 20 प्रति. इथेनॉल मिश्रित ईंधन से अपने वाहन आसानी से चला सकते हैं। अप्रैल 2025 से बने वाहन पूर्ण E20 अनुकूलित हैं, लेकिन 2023 से पहले के वाहनों में रबर पाटर्स, गैस्केट्स और प्लास्टिक पर इथेनॉल का बुरा असर हो सकता है। हालांकि, विशेषज्ञ कहते हैं कि यह मामूली है और सर्विसिंग में ठीक हो जाता है। E20 से ऑक्टेन नंबर बढ़ता है (91 से 95 तक), इसलिए एक्सलेरेशन बेहतर हो सकता है।

पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्या होगा



रजनीश कपूर

छले कुछ दिनों से केंद्र सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने और फ्लेक्स-प्यूल वाहनों को बढ़ावा देने का संकेत दिए हैं। पश्चिम एशिया संकेत के कारण ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने के बीच यह कदम तेल आयात पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने और स्वच्छ ईंधन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय की एक संयुक्त सचिव ने संकेत दिए कि सरकार जल्द ही E85 (85% इथेनॉल) से E100 (100% इथेनॉल) तक के वाहनों के टेस्टिंग नॉम्स अधिसूचित करने वाली है। ऑटोमोबिल्स पहले से ही इसके प्रोटोटाइप तैयार कर चुके हैं। देखा जा रहा है कि सरकार का यह फैसला आम आदमी को जेब, पर्यावरण और वाहनों पर क्या असर डालेगा? भारत ने 2025 में E20 कार्यक्रम को पूरा कर लिया है। अप्रैल 2026 तक देशभर में E20 पेट्रोल उपलब्ध है। अब सरकार E85 या इससे ऊंचे ब्लेंड की ओर आगे बढ़ रही है। फ्लेक्स-प्यूल वाहन किसी भी

अनुपात E20 से E100 तक में इथेनॉल चला सकते हैं। ब्राजील इसका सफल उदाहरण है। भारत में यह कदम ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। सरकार का दावा है कि EBP कार्यक्रम से अब तक 4.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल बचाया गया और 1.65 लाख करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा की बचत हुई। 2014 से अब तक 69.8 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन कम हुआ। लेकिन क्या यह आम आदमी के लिए फायदेमंद है? दावा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण को है। इथेनॉल नवीकरणीय स्रोत (गन्ना, मक्का, चावल) से बनता है। नीति आयोग के अनुसार, गन्ने से बने इथेनॉल से GHG उत्सर्जन 65% और मक्के से 50% कम होता है। पेट्रोलियम पर CO2 उत्सर्जन को 10% तक घटाने में मदद करेगा। E20 से CO2 में 6-8 प्रतिशत कमी आती है, जबकि E85 या E100 पर यह और ज्यादा। अध्ययनों से पता चलता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से वाहन प्रदूषण 20-30% तक घट सकता है। वहीं इसके नुकसान भी हैं। गन्ना आधारित इथेनॉल पानी-गहन है। एक लीटर इथेनॉल बनाने में करीब 2860 लीटर पानी लगता है। भारत में गन्ना पहले से ही 70 प्रतिशत सिंचाई पानी का उपभोग करता है। ज्यादा इथेनॉल के लिए अगर गन्ना या खाद्यान्न (मक्का, चावल) का इस्तेमाल बढ़ा तो 'फूड बनाम फ्यूल' विवाद खड़ा हो सकता है। इसके साथ ही भूमि उपयोग भी बढ़ेगा, मिट्टी की उर्वरता घट सकती है और कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ेगा। दूसरी पीढ़ी (2G) इथेनॉल (कृषि अपशेष से) पर जोर देने की

जरूरत है, जो पर्यावरण के लिए बेहतर है। कुल मिलाकर, अगर नीति सतर्क रही तो पर्यावरणीय फायदा साफ है, कम आयात, कम प्रदूषण, लेकिन पानी और भूमि प्रबंधन बिना तो नुकसान भी हो सकता है। उल्लेखनीय है कि इथेनॉल पेट्रोल से सस्ता है, इसलिए ब्लेंडिंग पेट्रोल का प्रति लीटर दाम कम रहता है। सरकार ने E20 के लिए कीमत कम रखने की सिफारिश की थी। लेकिन इथेनॉल की ऊर्जा घनत्व पेट्रोल से 30 प्रति. कम है, इसलिए इससे वाहन का माइलेज घटता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पुराने E20 वाहनों में E20 से 6-7 प्रतिशत (4-व्हीलर) या 3-4% (2-व्हीलर) माइलेज गिरावट हो सकती है। मतलब, अगर आपकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर की खपत करती है तो E20 पर 14.1-14.5 किलोमीटर हो जाएगी। गौरतलब है कि आप E85 या E100 चुन सकते हैं, अगर वह सस्ता हो। भारत में अभी इन्फ्रास्ट्रक्चर (अलग पंप) और कीमत निर्धारण स्पष्ट नहीं है। लंबे समय में इंसेंटिव से बचत हो सकती है। पुराने वाहन वाले उपभोक्ता (2012-2023 तक बने) को माइलेज नुकसान और संभवतः मटेनेंस खर्च बढ़ सकता है। कुल मिलाकर, जब पर तुरंत असर नकारात्मक हो सकता है, लेकिन अगर सरकार टैक्स छूट और सब्सिडी दे तो लंबे समय में यह फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं किसान समुदाय को इसका फायदा जरूर होगा, गन्ना और मक्का की खरीद बढ़ेगी, तो आय निश्चित ही बढ़ेगी।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

इस साल तपती धरती का कारण और इसका समाधान

उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व प. बंगाल जैसे राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इन राज्यों में कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक पहुंच गया है। पिछले दिनों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा हीटवेव अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी में लू चलने और तापमान में 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना को लेकर लोगों को सचेत किया है। पिछले कुछ वर्षों से लगभग हर साल गर्मी के तापमान में इजाफा होता ही जा रहा है। जीवन के लिए एकमात्र ग्रह पृथ्वी गत दो दशकों से ग्लोबल वार्मिंग का निरंतर प्रभाव झेल रही है। इसके अलावा भी वैज्ञानिकों द्वारा भारत में तेज गर्मी के और भी कई कारण बताए जा रहे हैं। इन कारणों में खासकर जलवायु परिवर्तन के अलावा हीट डोम और अल नीनो प्रभाव को रेखांकित किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उच्च दबाव प्रणाली गर्म हवा को जमीन के पास फंसाकर शकनश की तरह काम करती है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है। परिणाम स्वरूप compression heating से गर्मी और तीव्र हो जाती है। उधर पहले से हो रहा जलवायु परिवर्तन, सूखी मिट्टी और कम वनस्पति (वृक्ष कटाव) इसे बढ़ावा देते हैं। इसी को हीट डोम प्रभाव कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैसों से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। इसने हीटवेव की तीव्रता और इसकी अवधि दोनों को ही बढ़ा दिया है। बताया जा रहा

है कि 2026 में दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 92 शहर केवल भारत में हैं। इन गर्म क्षेत्रों में केवल दिन ही नहीं बल्कि यहां की रातें भी गर्म रहती हैं। इसे सीवियर गर्मी का चपेट में हैं। इन राज्यों में कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक पहुंच गया है। पिछले दिनों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा हीटवेव अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी में लू चलने और तापमान में 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना को लेकर लोगों को सचेत किया है। पिछले कुछ वर्षों से लगभग हर साल गर्मी के तापमान में इजाफा होता ही जा रहा है। जीवन के लिए एकमात्र ग्रह पृथ्वी गत दो दशकों से ग्लोबल वार्मिंग का निरंतर प्रभाव झेल रही है। इसके अलावा भी वैज्ञानिकों द्वारा भारत में तेज गर्मी के और भी कई कारण बताए जा रहे हैं। इन कारणों में खासकर जलवायु परिवर्तन के अलावा हीट डोम और अल नीनो प्रभाव को रेखांकित किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उच्च दबाव प्रणाली गर्म हवा को जमीन के पास फंसाकर शकनश की तरह काम करती है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है। परिणाम स्वरूप compression heating से गर्मी और तीव्र हो जाती है। उधर पहले से हो रहा जलवायु परिवर्तन, सूखी मिट्टी और कम वनस्पति (वृक्ष कटाव) इसे बढ़ावा देते हैं। इसी को हीट डोम प्रभाव कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैसों से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। इसने हीटवेव की तीव्रता और इसकी अवधि दोनों को ही बढ़ा दिया है। बताया जा रहा



है। गोया भारतीय शहरों में बढ़ता शहरीकरण बढ़ते तापमान के लिए 60 प्रतिशत तक जिम्मेदार है। और यही तापमान वृद्धि प्रति दशक 0.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करता है। शहरीकरण ने गर्मी में 90 प्रतिशत इजाफा किया है तथा रात्रिकालीन सतह तापमान लगभग 70-80 प्रतिशत तक बढ़ा है। मिसाल के तौर पर जमशेदपुर में शहरीकरण ने तापमान वृद्धि में 100 प्रतिशत योगदान दिया। ऐसे में सबसे ज्वलंत प्रश्न यही है कि आखिर तापमान वृद्धि की जिम्मेदार हमारी वर्तमान पीढ़ी क्या अपनी आने वाली नस्लों को भी ऐसी ही या इससे भी अधिक तपती पृथ्वी देकर जाएगी या इससे बचने के कुछ उपाय करना चाहेगी? इसके लिए सबसे पहले भारतीय शहरों में हरित आवरण को विस्तार देने की सख्त जरूरत है। हालांकि इसके लिए अनेक सरकारी योजनाएं व स्थानीय उपाय प्रभावी हैं जोकि शहरी गर्मी कम करने में हमारी सहायता करते हैं। इसके लिए

बाकायदा कार्य योजना बनाकर तथा वर्षाऋतु के आरंभ से ही सरकारी और नगर निकाय भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जा सकते हैं। कई राज्य इस दिशा में सक्रियता से काम भी कर रहे हैं। वृक्षारोपण को एक आंदोलन का रूप देने के लिए हर व्यक्ति अपने परिवार के शादी ब्याह, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, जन्म मृत्यु बरसी जैसे अवसरों पर वृक्षारोपण कर इन अवसरों को यादगार बनाने के साथ साथ जलवायु को बेहतर बनाने की दिशा में भी अपना कीमती योगदान दे सकता है। इसके अलावा हर व्यक्ति जहां जमीन कम हो वहां अपने घरों की छतों पर रूफ गार्डनिंग कर सकता है और वर्टिकल गार्डन भी लगा सकते हैं। अपने घरों के खुले क्षेत्र में अधिक से अधिक गमले लगाकर भी तापमान को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है तथा ताजी ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है। गौरतलब है कि कोरोना काल में जब देशभर में अचानक कोरोना प्रभावित लोगों के लिए ऑक्सीजन की कमी पैदा हुई थी उस समय लोगों को हरियाली और वृक्षारोपण की खूब याद आई थी। कई बीमार लोग तो छतों में पेड़ों के नीचे बैठकर स्वास्थ्य लाभ लेते देखे गए। इस आपदा ने ऑक्सीजन को लेकर लोगों में इतनी जागरूकता बढ़ाई कि उसी समय से गमलों व पौधों की नर्सरी का व्यवसाय कई गुना बढ़ गया।



निर्मल रानी

बाहरहाल भविष्य में तापमान वृद्धि से बचने व इसके दीर्घकालिक रूप से उपाय करने के साथ साथ तात्कालिक रूप से शरीर पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव से बचाव करना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले अपने शरीर को डिहाइड्रेशन से बचना और शरीर को हाइड्रेटेड रखना सबसे जरूरी है। इसके लिए बहुत सारा पानी पीना चाहिए और बार बार पीना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, सत् व ओआरएस जैसे शीतल पेय भी शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मददगार होते हैं और डिहाइड्रेशन रो. कते हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

